



विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की: भारत को हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग रिज में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए विशेष अधिकार मिले

भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ दो पीएमएस अन्वेषण अनुबंध प्राप्त करने वाला पहला देश बना; अग्रणी निवेशक के रूप में मिली मान्यता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया डीप ओशन मिशन, जो समुद्र तल खनिज अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी विकास और भारत की 'ब्लू इकोनॉमी पहल' को मजबूत करने पर केंद्रित है

आईएसए के साथ 30 साल की साझेदारी की पुष्टि की; गोवा में 8वें आईएसए वार्षिक ठेकेदार सम्मेलन की मेजबानी करेगा

प्रविष्टि तिथि: 20 SEP 2025 4:11PM by PIB Delhi

केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (आईएसए) के बीच एक नए 15-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। यह अनुबंध हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग रिज के आवंटित 10,000 वर्ग किमी क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (पीएमएस) की खोज के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है।

इसके साथ, भारत पीएमएस अन्वेषण के लिए आईएसए के साथ दो अनुबंध करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जो गहरे समुद्र के संसाधन अन्वेषण में अपनी अग्रणी भूमिका और हिंद महासागर में अपनी रणनीतिक उपस्थिति की पुष्टि करता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह नया अनुबंध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए डीप ओशन मिशन के विज्ञान को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य समुद्र तल में खनिज अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी विकास और भारत की 'ब्लू इकोनॉमी पहलों' को मजबूत करना है। उन्होंने आगे कहा, "कार्ल्सबर्ग रिज में पीएमएस अन्वेषण के लिए विशेष अधिकारों को औपचारिक रूप देकर, भारत ने गहरे समुद्र में अनुसंधान और अन्वेषण में अपनी अग्रणी स्थिति को और मजबूत किया है। इससे हमारी समुद्री उपस्थिति बढ़ेगी और भविष्य में संसाधनों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण होगा।"

पॉलीमेटेलिक सल्फाइड में लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसे मूल्यवान धातु होते हैं, और ये समुद्री पपड़ी से निकलने वाले गर्म हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों से बनते हैं। उनकी रणनीतिक और वाणिज्यिक क्षमता ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे भारत गहरे समुद्र के संसाधन अन्वेषण में सबसे आगे खड़ा है।

आईएसए के साथ भारत की लंबे समय से चली आ रही साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि भारत अंतरराष्ट्रीय जल में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल अन्वेषण के लिए क्षेत्र प्राप्त करने वाला पहला देश था और इसे "अग्रणी निवेशक" के रूप में नामित किया गया था। अब दो पीएमएस अनुबंधों के साथ- एक सेंट्रल इंडियन रिज और साउथवेस्ट इंडियन रिज में और दूसरा कार्ल्सबर्ग रिज में- भारत के पास अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल में पीएमएस अन्वेषण के लिए आवंटित सबसे बड़ा क्षेत्र भी है।

डॉ. सिंह ने कहा, "आईएसए के साथ भारत का 30 साल का जुड़ाव गर्व का स्रोत रहा है, और जैसा कि आईएसए अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रहा है, भारत मानवता की आम विरासत के लिए अपने जनादेश को पूरा करने के लिए आईएसए के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।" उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत 18-20 सितंबर तक गोवा में 8वीं आईएसए वार्षिक ठेकेदार बैठक की मेजबानी करेगा, जो समुद्र तल अन्वेषण में भारत की अग्रणी भूमिका में एक और मील का पत्थर साबित होगी।

इस अवसर पर बोलते हुए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन ने कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और उसके स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर), गोवा के लिए दूसरे पीएमएस अन्वेषण अनुबंध पर हस्ताक्षर करना एक गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा, "यह भारत को आईएसए का पहला सदस्य राज्य और सरकारी ठेकेदार बनाता है जिसके पास दो पीएमएस अन्वेषण अनुबंध हैं। यह भी गर्व की बात है कि भारत के पास अब पीएमएस अन्वेषण के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल में विश्व स्तर पर सबसे बड़ा क्षेत्र आवंटित है।"

डॉ. रविचंद्रन ने कहा कि भारत अज्ञात समुद्र तल पारिस्थितिकी प्रणालियों के अधिक वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न करने और मानवता के लाभ के लिए खनिज संसाधनों का दोहन करते हुए समुद्री पर्यावरण की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईएसए के साथ अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए तत्पर है।





पीके/केसी/केजे

(रिलीज़ आईडी: 2169152)

इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , Marathi , Tamil , Malayalam